सशक्तीकरण का संकल्प

अब निर्णायक भूमिका में हैं महिलाएं

रघुवर दास
मुख्यमंत्री, झारखंड

हमारे देश में महिलाओं का दर्जा हमेशा ऊंचा रहा है. वैदिक काल की विदूषी महिलाओं ने अपने ज्ञान, मेधा और कर्मचेतना से इस राष्ट्र को सींचने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी. हाल ही में नवरात्र और दीपावली का पर्व संपन्न हुआ है. इन पर्वों में महिलाओं के यथोचित सम्मान, आह्वान और उनके सबल अस्तित्व का संदेश छुपा हुआ है. सशक्त महिलाएं पूरे समाज को एक सूत्र में बांध सकती हैं. विपत्तियों को साध सकती हैं और देश-समाज को अपनी संवेदनशीलता से नयी राह दिखा सकती हैं. हम मानते हैं कि महिला सशक्तीकरण महज एक नारा नहीं, बल्कि हमारा दायित्व है. महिलाओं के हर क्षेत्र में आगे आने और राष्ट्र के विकास में कंधे से कंधा मिला कर काम करने से ही राष्ट्र का कल्याण निहित है. कई पितृसत्तात्मक परिवारों में अपेक्षाकृत महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता, लेकिन हाल के वर्षों में हमारे समाज में महिला सशक्तीकरण की नयी चेतना उभरी है. इसके परिणामस्वरूप हमारे समाज में महिलाएं अब निर्णायक भूमिका में दिख रही हैं. यह परम संतोष का विषय है.

झारखंड जैसे राज्य में खास कर आदिवासी समाज में महिलाओं को सबल बनाने और उनके परिवार में निर्णायक भूमिका निभाने के सारे अवसर मौजूद हैं. हमारे पुरखों ने महिलाओं को पुरुषों से कभी कमतर नहीं समझा. यही कारण है कि वे खेत से लेकर फैक्ट्री, कॉरपोरेट जगत से लेकर कारोबार की दुनिया में तेजी से जगह बना रही हैं. हमारी सरकार ने दो साल पहले जब पहली बार आम बजट में जेंडर बजट का प्रावधान रखा था, तो उसके पीछे सोच यही थी कि राज्य के हर वर्ग की महिलाओं को सबल कर उनके हाथों में निर्णायक शक्ति दी जाये, ताकि राज्य की आधी आबादी अपने बूते खड़ी हो सके. हमने राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना, स्कूली बच्चियों को साइकिल योजना, गरीब महिलाओं को धुएं से आजादी देने के लिए उज्ज्वला योजना, महिलाओं के नाम पर एक रुपये में जमीन की रजिस्ट्री, कामकाजी महिलाओं के लिए आवास, नौकरीशुदा महिलाओं के बच्चों के लिए पालना घर, आर्थिक प्रोत्साहन के लिए ऑटो रिक्शा का लाइसेंस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने के लिए पुख्ता स्वास्थ्य योजना, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ पूरे राज्य में व्यापक जागरूकता अभियान जैसी योजनाएं चलायी गयी हैं. ये सिर्फ योजनाएं ही नहीं हैं, बल्कि ये राज्य में युवतियों एवं महिलाओं के समग्र विकास के सूत्र हैं, क्योंकि इन योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है. इससे राज्यभर में महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार देखा जा रहा है.

हमने राज्य में गरीब एवं ग्रामीण परिवेश की बच्चियों के लिए उड़ान स्कॉलरशिप के माध्यम से पायलट ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया है, दूसरी ओर मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान के तहत गांव के घरों के बाहर नेमप्लेट पर बेटियों के नाम लिखे जाने की योजना पूरे राज्य में चल रही है. हम 14 से 24 साल की पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को फिर से पढ़ने व कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए तेजस्विनी योजना चला रहे हैं. इसमें पढ़ाई या ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सरकार द्वारा तीन किश्तों में 10 हजार रुपये दिये जाते हैं. इसी तरह से गरीब और महिलाओं के उत्थान के लिए जोहार योजना शुरू की गयी है. राज्य के 17 जिलों के 68 प्रखंडों में यह योजना चालू की गयी है. 1400 करोड़ की इस योजना के तहत 3400 महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराया जायेगा.

मेरा मानना है कि उपरोक्त सारे प्रयास ऐसे हैं, जो महिलाओं के स्वाभिमान को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं. हमारी बेटियां व महिलाएं कहीं से भी कमतर नहीं हैं. उन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन और आत्मविश्वास के बूते कई सराहनीय और हैरतअंगेज काम कर दिखाये हैं. उन्हें सिर्फ प्रोत्साहित करने की जरूरत है. हमारा संकल्प है कि हम महिला सशक्तीकरण एवं विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेंगे.

चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित करते मुख्यमंत्री, स्थानीय विधायक व अन्य.

महिलाओं को आगे बढ़ाने पर जोर

- राज्य में पहली बार आम बजट में जेंडर बजट का प्रावधान, जिसमें हर वर्ग की महिलाओं को सबल कर उनके हाथों में निर्णायक शक्ति देने पर जोर
- **राज्य में युवतियों एवं महिलाओं के समग्र विकास के सूत्र हैं कई योजनाएं इसमें उज्ज्वला योजना, महिलाओं के नाम एक रुपये में जमीन की रजिस्ट्री, कामकाजी महिलाओं के लिए आवास, नौकरीशुदा महिलाओं के बच्चों के लिए पालना घर, आर्थिक प्रोत्साहन के लिए ऑटो रिक्शा का लाइसेंस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिशु लिंग अनुपात में कमी रोकने के लिए स्वास्थ्य योजना, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता अभियान आदि मुख्य हैं**
- ग्रामीण बच्चियों के लिए उड़ान स्कॉलरशिप के माध्यम से पायलट ट्रेनिंग कार्यक्रम
- **मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान में घरों के बाहर बेटियों के नेमप्लेट लगे**
- तेजस्विनी योजना के तहत बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को दोबारा पढ़ने व कौशल विकास का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है. पढ़ाई या ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सरकार द्वारा तीन किश्तों में 10 हजार रुपये दिये जाते हैं
- **राज्य के 17 जिलों के 68 प्रखंडों में तेजस्विनी योजना में 3400 महिला स्वयं सहायता समूहों को उत्पादों के लिए बाजार की सुविधा**